

जीएसटी संग्रह 1.94 लाख करोड़

वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीने में सकल 6.2 फीसदी बढ़ा

नयी दिल्ली, 01 जून आयात पर प्राप्त कर राजस्व में 19 प्रतिशत के जबरदस्त उछाल के कारण इस साल मई में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.94 लाख करोड़ के पार दर्ज किया गया।

वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि मई में कुल जीएसटी संग्रह 1,94,184 करोड़ रुपये रहे जो पिछले साल मई के मुकाबले 3.2 प्रतिशत अधिक है। इसमें घरेलू जीएसटी संग्रह 2.6 प्रतिशत घटकर 1,34,530 करोड़ रुपये रह गया जबकि आयातित वस्तुओं पर सकलित जीएसटी की राशि 19.1



वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीने में सकल जीएसटी संग्रह 6.2 फीसदी बढ़कर 4,36,887 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। इसमें 59,063 करोड़ रुपये की रिफंड की राशि घटा देने पर शुद्ध जीएसटी संग्रह 3,77,824 करोड़ रुपये बना है। रिफंड में सालाना 10.9 प्रतिशत और शुद्ध संग्रह में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

प्रतिशत बढ़कर 59,654 करोड़ रुपये दर्ज की गयी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित वस्तुओं, विशेषकर कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज उछाल के कारण उन पर जीएसटी की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ी है।

सरकार ने कुल 27,281 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दिया जो सालाना आधार पर 2.6 प्रतिशत अधिक है। इसमें घरेलू रिफंड 4.3 फीसदी कम होकर 17,030 करोड़ रुपये और निर्यातकों को दिया गया रिफंड 16.6 प्रतिशत बढ़कर 10,250 करोड़ रुपये रहा।

रुपया 34 पैसे कमजोर

मुंबई, 01 जून. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को 34 पैसे टूट गया और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.19 रुपये का बोला गया। भारतीय मुद्रा पिछले दो कारोबारी दिवस पर मजबूती के साथ बंद हुई थी। पिछले सप्ताहोंत यह 73 पैसे चढ़कर 94.85 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी। रुपये की शुरुआत आज आठ पैसे की गिरावट में 94.93 रुपये प्रति डॉलर पर हुई। हालांकि कुछ ही देर में यह 94.73 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ लेकिन बाद में फिर टूट गया। कारोबार की समाप्ति तक यह 95.19 रुपये तक उतरकर अंत में उसी स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक में डॉलर सूचकांक के 0.5 प्रतिशत तक मजबूत होने से भारतीय मुद्रा पर दबाव रहा।

मई में बिजली खपत 11.55% बढ़ी

बिजली की अधिकतम मांग 270.82 गीगावाट के नए शिखर पर

नई दिल्ली, 1 जून। देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच मई 2026 में बिजली की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। एयर कंडीशनर,

रिकॉर्ड 164.98 अरब यूनिट पहुंची
भीषण गर्मी से एसी-कूलर की मांग बढ़ी

कूलर और अन्य शीतलन उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की मांग और खपत दोनों नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।

मई में देश की कुल बिजली खपत 11.55 प्रतिशत बढ़कर 164.98 अरब यूनिट हो गई, जबकि अधिकतम बिजली मांग

मई 2024 में अधिकतम मांग 250 गीगावाट थी पार

विशेषज्ञों के अनुसार, तापमान में वृद्धि के चलते घरों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य शीतलन उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसका सीधा असर बिजली की मांग पर पड़ा है। मई के दौरान देश की अधिकतम बिजली मांग बढ़कर 270.82 गीगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि मई 2025 में यह 230.99 गीगावाट थी। मई 2026 में लगातार चार दिनों तक बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। 18 मई को अधिकतम मांग 257.37 गीगावाट दर्ज की गई। इसके बाद 19 मई को यह बढ़कर 260.45 गीगावाट हो गई। 20 मई को मांग 265.44 गीगावाट तक पहुंची और 21 मई को 270.82 गीगावाट के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले 25 अप्रैल 2026 को भी बिजली की मांग 256.11 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। गौरतलब है कि मई 2024 में देश की अधिकतम बिजली मांग पहली बार लगभग 250 गीगावाट के स्तर को पार कर गई थी।

270.82 गीगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। देश में लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण मई 2026 में बिजली की खपत और मांग दोनों ने नए रिकॉर्ड बनाए।

महीने के पहले दिन सोना 1,561 और चांदी 1,485 सस्ती

नई दिल्ली, 1 जून। जून महीने के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में शुरुआती कारोबार के दौरान सोना 1,561 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया, जबकि चांदी में 1,485 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखी गई।

एमसीएक्स में आई बड़ी गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और निवेशकों की बिकवाली के दबाव के चलते दोनों कीमतों धातुओं के भाव नीचे आए। एमसीएक्स पर 5 अगस्त डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र



में 1,60,911 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोमवार को यह 1,60,193 रुपये पर खुला और शुरुआती कारोबार में 1,59,350 रुपये तक फिसल गया। सुबह 9:55 बजे सोना 1,210 रुपये यानी 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,59,701 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता देखा गया।

अहमदाबाद रेल मंडल का मई 2026 में रिकॉर्ड प्रदर्शन

माल लदान, राजस्व और यात्री सेवाओं में दर्ज की रिकॉर्ड वृद्धि

अहमदाबाद 1 जून. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के परिचालन विभाग ने मई 2026 के महीने में माल लदान (फ्रेट लोडिंग), राजस्व सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और यात्री सेवाओं के मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।

वित्तीय एवं माल लदान की मुख्य विशेषताएं राजस्व में वृद्धि: मंडल ने मई 2026 में 517.34 करोड़ रुपये का माल भाड़ा राजस्व अर्जित किया। रिकॉर्ड लदान: इस महीने कुल 3.93 मिलियन टन (स्को) माल का लदान किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 3.83



मिलियन टन की तुलना में 2.6% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान प्रतिदिन औसतन 2639.48 वैगनों का लदान किया गया। प्रमुख वस्तुएं (कमोडिटी): मई 2025 की तुलना में कई प्रमुख वस्तुओं के लदान में भारी उछाल देखा गया, जिसमें नमक (औद्योगिक नमक सहित) में

+31.53%, उर्वरक (फर्टिलाइजर) में +13.02% और अन्य वस्तुओं में +22.64% की वृद्धि दर्ज की गई। गांधीधाम क्षेत्र का नेतृत्व: माल लदान के मामले में गांधीधाम क्षेत्र सबसे आगे रहा, जहां प्रतिदिन औसतन 1936.97 वैगनों का लदान किया गया।

कच्छ से कश्मीर' बिजनेस पहल: बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के प्रयासों से गांधीधाम क्षेत्र ने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। 5 मई 2026 को, मंडल ने 'कच्छ-टू-कश्मीर' माल परिवहन पहल के तहत 20 ड्रह वैगनों में भीमास से बारी ब्राह्मण) और अनंतनाग के लिए खाद्य तेल की पहली खेप भेजी गई।

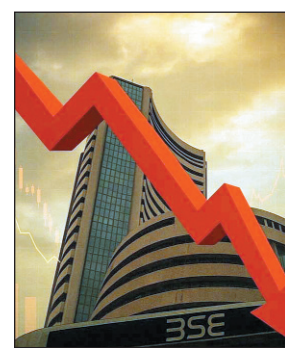
बुनियादी ढांचा विकास और परिचालन क्षमता- नई वाई-कनेक्टिविटी चांदखेड़ा-गांधीग्राम वाई-कनेक्टिविटी के चालू होने के बाद पहली बार इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ।

कच्चे तेल में तेजी से लुढ़के शेयर बाजार

सेंसेक्स आठ सप्ताह के निचले स्तर पर

मुंबई, 01 जून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से घरेलू शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले दिन शुरुआती तेजी के बाद गिरावट देखी गयी और बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आठ सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स की शुरुआत 427 अंक की तेजी में हुई थी, लेकिन दोपहर बाद यह लाल निशान में चला गया। कारोबार की समाप्ति पर यह 508.40 अंक (0.68 प्रतिशत) लुढ़ककर 74,267.34 अंक पर बंद हुआ। यह 06 अप्रैल के बाद का इसका निचला स्तर है।



एनएसई में जिन 3,452 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें से 2,202 के शेयर गिरावट में और 1,150 के बढ़त में रहे। अन्य 100 कंपनियों के शेयर दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद अंततः अपरिवर्तित रहे। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 24 के शेयर लाल निशान रहे। हिंदुस्तान यूनिलिवर का शेयर 2.83 प्रतिशत लुढ़क गया। आईटीसी में 2.53 फीसदी, एनटीपीसी में 2.15 और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.10 प्रतिशत की गिरावट रही। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1.95 फीसदी, अल्ट्राटेक सीमेंट का 1.87, बजाज फाइनेंस और टैट दोनों के 1.74 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।

समय से लिवाली चल रही है। एफएमसीजी, बैंकिंग, वित्त, ऑटो, रियल्टी, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समूहों में ज्यादा गिरावट रही

मई में ऑटो सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार

एसयूवी और ट्रैक्टर बिक्री ने बनाए नए रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 1 जून। घरेलू मांग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और एसयूवी वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के दम पर भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने मई 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और टोयोटा जैसे प्रमुख कंपनियों ने विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की। पैसंजर वाहनों के साथ-साथ ट्रैक्टर, कर्मशियल वाहनों और हाइब्रिड कारों की मांग भी मजबूत रही, जिससे ऑटो सेक्टर ने नए रिकॉर्ड बनाए। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने मई में कुल 2,42,688 वाहनों की



बिक्री कर अपने इतिहास की सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की। इसमें घरेलू बाजार में 1,93,535 वाहन बिके जबकि 41,914 वाहनों का निर्यात किया गया। दूसरी ओर हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री 9.1 प्रतिशत बढ़कर 47,837 यूनिट पर पहुंच गई, जबकि कुल बिक्री 61,137 यूनिट रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी

मजबूत प्रदर्शन करते हुए कुल ऑटो बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने घरेलू बाजार में 58,021 यूटिलिटी व्हीकल्स बेचे। कर्मशियल व्हीकल सेगमेंट में बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 24,079 यूनिट रही। वहीं ट्रैक्टर कारोबार में 23 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि के साथ कंपनी ने घरेलू बाजार में 47,845 ट्रैक्टर बेचे।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल, 2026 में बढ़ कर 118.9 अंक रहा जो

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अप्रैल में 4.9%

2022-23 की नयी श्रृंखला का मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी

नयी दिल्ली, 01 जून. सरकार द्वारा आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की नयी श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 4.9 की वृद्धि दर्ज की गयी. पिछले वर्ष इसी माह औद्योगिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत और इस वर्ष मार्च में 3.2 प्रतिशत थी।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल, 2026 में बढ़ कर 118.9 अंक रहा जो

रिपोर्ट के मुताबिक आलोच्य माह में विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहा और 23 में से 17 उद्योग समूहों के उत्पादन में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गयी. मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर निर्माण उद्योग की वृद्धि दर 12.7 प्रतिशत, विद्युत उपकरण निर्माण क्षेत्र की वृद्धि 19.2 प्रतिशत और मशीनरी एवं उपकरण निर्माण उद्योग की वृद्धि 12.9 अप्रैल में प्राथमिक वस्तु उद्योग की वृद्धि 0.8 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तु उद्योग की 16.0 प्रतिशत तथा मध्यवर्ती वस्तुएं बनाने वाले क्षेत्र की वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही. इस दौरान अदरसरचना/निर्माण क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं का उत्पादन सालाना आधार पर 7.1 प्रतिशत ऊंचा रहा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उद्योग की वृद्धि 4.3 प्रतिशत तथा गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की वृद्धि 2.8 प्रतिशत रही. सरकार का कहना है कि पूंजीगत वस्तुओं में 16 प्रतिशत की वृद्धि निवेश गतिविधियों और औद्योगिक विस्तार का संकेत देती है।

अप्रैल 2025 में था. इस वर्ष अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि 6.2 प्रतिशत रही, जबकि बिजली और गैस अपूर्ण क्षेत्र का उत्पादन 4.9 प्रतिशत और सीकरेज एवं

अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का उत्पादन 6.6 प्रतिशत रहा. आलोच्य माह में खनन एवं खनन उत्पाद क्षेत्र का उत्पादन एक साल पहले से 5.1 प्रतिशत घट गया.

समाचार विशेष

बंगाल के बाद अब झारखंड पर नजर

दुमका. पश्चिम बंगाल में प्रखर हिंदुत्व के मुद्दे पर मिली प्रचंड जोत के बाद भाजपा की रणनीतिक नजर अब झारखंड पर टिक गई है. पार्टी मतांतरण, डि-लिस्टिंग और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर विरोधी दलों पर चौतरफा हमला करने की तैयारी में जुटी है. जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 24 मई को नई दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. राजकिशोर हांसदा ने कहा कि देश में जनजातीय समाज की

करीब 750 श्रेणियां हैं, जबकि झारखंड में इनकी संख्या 35 से बढ़कर 37 हो गई है. दिल्ली में आयोजित समागम में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जनजातीय समाज की भागीदारी ऐतिहासिक रही. डॉ. हांसदा ने कहा कि जनजाति सुरक्षा मंच लंबे समय से मतांतरण करने वालों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने की मांग उठा रहा है. इसके लिए संविधान की धारा 342 में संशोधन की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा सांस्कृतिक समागम में देशभर से पहुंचे करीब डेढ़ लाख जनजातीय समुदाय के लोगों की भीड़ से भाजपा रणनीतिकार उत्साहित हैं. जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. राजकिशोर हांसदा ने कहा कि देश में जनजातीय समाज की

भाजपा की 2027 यूपी की चुनावी रणनीति

जियो टैगिंग संग ऑनलाइन उपस्थिति से कार्यकर्ताओं पर नजर

प्रयागराज. राजनीति के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं. तकनीक का समावेश होने के साथ आचार व्यवहार में बदलाव हो रहा है. भाजपा इसमें सब से आगे है. ऑनलाइन उपस्थिति अब तक सरकारी कार्यालयों में होती थी लेकिन अब संगठन की बैठकों व अन्य कार्यक्रमों में इसे अपनाया जा रहा है. इससे शीघ्र नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं पर नजर रखने, सक्रिय लोगों की पहचान करने, तकनीक के साथ कदमताल करने वाली पीढ़ी तैयार करने का प्रयास करेगा. भाजपा ने वर्ष 2023 में सरल

एप लांच किया. इससे संगठनात्मक जानकारी के प्रबंधन और बूथ स्तर की गतिविधियों की निगरानी की रूपरेखा बनाई गई. राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया. इसपर पदाधिकारियों का संपूर्ण विवरण अपलोड किया गया. इस पर शैक्षणिक योग्यता, बूथ मतदाताओं के विवरण के साथ बूथ समिति, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की जानकारी भी

अपडेट की जाती है. ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी - नई व्यवस्था के तहत अब पार्टीजनों को शक्ति केंद्रों पर होने वाली बैठकों, प्रशिक्षण अभियानों व अन्य योजना बैठकों में शामिल लोगों को जियो टैगिंग के साथ ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस पर अमल भी शुरू हो गया है. काशी प्रांत के मीरजापुर, भदोही, गाजीपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मछलीशहर, सोनभद्र, अमेठी, प्रयागराज, चंदौली में हुए पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण

विस चुनाव 2027 में विजय का लक्ष्य

भाजपा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान के प्रदेश सह संयोजक डॉ. शैलेश पांडेय का कहना है कि असम और बंगाल विजय के बाद पार्टी का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश पर है. विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में विजय का लक्ष्य लेकर शीघ्र नेतृत्व ने वृहद रचना शुरू की है. विपक्ष को घेरने के साथ पार्टीजनों को कप्तन, दायित्व देने से आगे बढ़ते हुए मूल कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने का प्रयास है. अभियान में कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन पंजीयन के साथ उपस्थिति भी आनलाइन ली गई.

नए चेहरे क्या दिखेंगे सरकार में?

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से मंत्रिपरिषद की बैठक की है और मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हुई है तब से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही. 20 जून तक फेरबदल की बात कही जा रही है और उससे पहले नितिन नबीनी को टीम के गठन की चर्चा है. कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के कई मंत्री, अनुभव हैं और जो हर जगह चुनाव जिताने में महारत रखते हैं उनको संगठन में भेजने की चर्चा है. कहा जा रहा है कि सरकार में नए चेहरों के लिए जगह बनाई जा

रही है. उत्तर प्रदेश और बिहार से नए चेहरे सरकार में लाए जा सकते हैं. चर्चा तो राधक चड्ढा को भी मंत्री बनाने की थी. लेकिन उनको पिछले दिनों संसद का याचिका समिति का अध्यक्ष बना दिया गया. उसके बाद उनकी चर्चा थम गई है. फिर सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी छोड़ कर भाजपा में आए नेताओं में से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के मंत्री बनने की चर्चा है. इसी तरह उत्तर प्रदेश से एक दूसरे ब्राह्मण नेता हरीश द्विवेदी की भी चर्चा हो रही है.



तुष्टिकरण का दौर अब समाप्त होने वाला

मतांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लगातार उठाते रहे गोष्ठा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मान रही है. डॉ. दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ और मतांतरण जैसे मुद्दों पर तुष्टिकरण की राजनीति का दौर अब समाप्त होने वाला है और आने वाले समय में इन मुद्दों पर राजनीति करने वाले दलों को जनता जवाब देगी।

उन्होंने कहा कि यदि भाजपा मंच की मांगों के समर्थन में है, तो उसे इस संबंध में संशोधन विधेयक लाना चाहिए. जनजाति सांस्कृतिक समागम के जरिए मंच ने केंद्र सरकार, जनजातीय समाज विरोधी राजनीतिक दलों और मिशनरियों को अपनी एकजुटता और ताकत का एहसास कराया है.

महाराष्ट्र में महा-संग्राम! एनसीपी के 2 नाम खारिज

मुंबई. महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सत्ता का खेल सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हर कुर्सी के पीछे ताकत, दबदबा और भविष्य की रणनीति छिपी हुई है. सुनेत्रा पवार के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद खाली हुई एक सीट ने महायुक्ति के भीतर बड़ा भूचाल ला दिया है. भाजपा और अजित पवार की एनसीपी के बीच अंदरखाने चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने एनसीपी की तरफ से सुझाए गए दो नामों को ही खारिज कर दिया. इससे साफ संकेत मिल रहा है कि

राज्यसभा की यह सीट सिर्फ औपचारिक चुनाव नहीं, बल्कि महागठबंधन के भीतर ताकत की असली परीक्षा बन चुकी है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा अब एनसीपी पर अपना दबाव बढ़ाना चाहती है, ताकि आने वाले विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में पूरी कमान उसके हाथ में रहे. इस पूरे घटनाक्रम ने एनसीपी के भीतर भी नई हलचल पैदा कर दी है.

छान भुजबल अचानक सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं. माना जा रहा है कि दिल्ली की राजनीति में एंटी के जरिए वह खुद को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं. लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है. अगर भुजबल राज्यसभा जाते हैं तो महाराष्ट्र कैबिनेट में उनका मंत्री पद खाली होगा और यहीं से असली सत्ता संघर्ष शुरू हो जाएगा. धनंजय मुंडे से लेकर समीर भुजबल तक कई नेता अपनी-अपनी

राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं. ऐसे में एक राज्यसभा सीट अब पूरे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल का कारण बनती दिख रही है. सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा उपचुनाव को लेकर महायुक्ति के भीतर लगातार बैठकें हो रही हैं. सूत्रों के मुताबिक एनसीपी ने पहले अविनाश आदिक और सुबोध मोहिते के नाम भाजपा नेतृत्व के सामने रखे थे. लेकिन भाजपा ने दोनों नामों पर असहमति जता दी. इसके बाद से गठबंधन के भीतर असहज स्थिति बन गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस सीट के जरिए महायुक्ति में अपनी निर्णायक भूमिका दिखाना चाहती है.

मंत्री पद को लेकर शुरू हुई अंदरूनी लड़ाई

एनसीपी के भीतर इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भुजबल राज्यसभा जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा. सूत्रों के मुताबिक समीर भुजबल को अगर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं. इससे पार्टी के भीतर कई नेता नाराज बातए जा रहे हैं. यही वजह है कि अजित पवार के सामने संगठन को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बन गया है. राज्य की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे के संभावित इस्तीफे को लेकर सामने आ रहा है. चर्चा है कि अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है तो वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.

